

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246144
SG-DL-E-29052023-246144असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]	दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ ज्येष्ठ 8, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
No. 165]	DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 78

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 मई, 2023

F.NO. F(12)/Policy/AS/STA/2016/49928.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 की धारा 67 की उप धारा (3) और धारा 2 की धारा (41) के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 के अनुसरण और अनुपालन में जारी की गई अधिसूचना सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 26 नवंबर, 2020 के क्रमांक एस.ओ.4251 (ई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एतद्वारा मसौदा योजना प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है, '(द दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर) (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद उक्त मसौदा योजना पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली -110054 या ईमेल commpt@nic.in और tptassta@gmail.com पर संबोधित किए जाएंगे।

मसौदा योजना:**1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ:**

- (क) इसे "दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023" कहा जाएगा।
- (ख) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए वैध एग्रीगेटर लाइसेंस के तहत संचालित सभी प्रीमियम बसों पर लागू होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संचालित होती हैं।
- (ग) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ:

(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59).
- (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कथित योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के संबंध में अपील पर विचार करने के उद्देश्य से है;
- (ग) "ऐप" का अर्थ लाइसेंस धारक या लाइसेंस धारक की ओर से किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस है जिसे कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ उप सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उक्त योजना के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्रदान/नवीनीकृत/ निलंबित/रद्द करेगा;
- (ङ) "लाइसेंस धारक" का अर्थ एक व्यक्ति या संस्था है जो इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी लाइसेंस रखता है;
- (च) "पैसेंजर मैनिफेस्ट" का अर्थ है उन व्यक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड जो यात्रा के दौरान प्रीमियम बस में यात्रा करने की संभावना रखते हैं और जिनकी ओर से लाइसेंस धारक बस के मालिक के साथ व्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करता है, या इस योजना के अनुसार संपूर्ण रूप से वाहन किराए पर लेने के लिए उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति;
- (छ) "परमिट" का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम -1988 की धारा -74 के तहत परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक वैध अनुबंध कैरिज परमिट है;
- (ज) "प्रीमियम बस" का अर्थ निम्नलिखित सुविधाओं के साथ 12 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाला एक लक्जरी सार्वजनिक सेवा वाहन है
- एयर कंडीशनर, वाई-फाई, जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन, 2 x 2 सीटें, रिक्लाइनिंग सीटें या समय-समय पर योजना में शामिल कोई अन्य विनिर्देश / सुविधा।
- विवश परिस्थितियों में उचित समझी जाने वाली अन्य विशिष्टताओं/शर्तों को परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर शामिल किया जाएगा;
- (झ) "स्टैंड फीस" का अर्थ परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए बस कतार आश्रयों का उपयोग करने के लिए निर्धारित शुल्क है;
- (2) इस योजना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन यहां परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

3. एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान करने की पात्रता:

- (1) लाइसेंस धारक न्यूनतम 50 प्रीमियम बसों के एक बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा, जिसे लाइसेंस प्रदान करने के दिन से 90 दिनों के भीतर चालू किया जाना है।

- (2) आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रीमियम बसों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या की आवश्यकता को संशोधित किया जा सकता है।
- (3) लाइसेंस धारक, यात्रियों के लिए और उनकी ओर से, संभावित मार्ग निर्धारित कर सकता है, जिस पर उसके द्वारा संचालित वाहन चलेंगे।
बशर्ते कि यातायात पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत एजेंसी या मार्ग को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा स्व-निर्धारित संभावित मार्गों पर आपत्ति नहीं की जा सकती है, यदि आपत्ति है, तो स्व-निर्धारित मार्ग समाप्त हो जाएंगे।
- (4) आम जनता की जानकारी के लिए ऐसे मार्गों का विवरण मोबाइल या वेब आधारित एप्लिकेशन पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (5) जिस मार्ग पर बस का संचालन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन/समाप्ति लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी स्थिति में बिना सक्षम प्राधिकारी को सात दिन पूर्व सूचना दिये बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा। मार्ग परिवर्तन के प्रभाव की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मोबाइल या वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से आम जनता को भी दी जाएगी।
- (6) लाइसेंस धारक द्वारा इस तरह के किसी भी मार्ग को समाप्त नहीं किया जाएगा, यदि उस मार्ग के लिए अग्रिम बुकिंग/पुष्टि की जाती है, सेवा समाप्त करने की किसी अत्यावश्यकता के मामले में प्रदान की गई बुकिंग राशि यदि अग्रिम में प्राप्त की जाती है तो उसी दिन यात्री को वापस कर दी जाएगी।
- (7) लाइसेंस किसी भी फर्म या संस्था को, जो या तो दिवालिया, या किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण या भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध हो, नहीं दिया जाएगा।
- (8) लाइसेंस धारक के पास सक्षम प्राधिकारी को सूचना के तहत विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर कॉर्पोरेट या शाखा कार्यालय होगा।
- (9) इस योजना के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंस धारक को निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ सार्वजनिक परिवहन/साझा परिवहन में वाहनों के संचालन/प्रबंधन/वाहनों का कम से कम 03 वर्ष का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए:-
(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (प्रत्येक वर्ष) के दौरान न्यूनतम 100 यात्री बसों का बेड़ा; या
(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (प्रत्येक वर्ष) के दौरान न्यूनतम 1000 यात्री कारों का बेड़ा; या
(ग) यात्री कारों और बसों के मिश्रित बेड़े के मामले में, कुल न्यूनतम बेड़े कम से कम 100 बसों के बराबर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 10 कारों को 1 बस के बराबर माना जाएगा।
- (10) लाइसेंस धारक इस योजना के तहत लाइसेंस जारी करने के अनुरोध के साथ गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक वचनबद्धता देगा कि वह केंद्रीय मोटर वाहन नियम -1989 या दिल्ली मोटर वाहन नियम -1993 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में निर्धारित सभी लागू प्रावधानों का पालन करेगा।
- (11) लाइसेंस धारक के पास संचालन को नियमित करने के लिए और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अनुबंध कैरिज परमिट होना चाहिए जो कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम -1988 के अध्याय-VIII & XIII और दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 नियमों के अध्याय-VIII में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, लागू होगा।
- (12) लाइसेंस धारक इस योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परमिट धारक के वाहन के उपयोग के लिए एक परमिट धारक के साथ एक अनुबंध करेगा और ऐसा अनुबंध पूरे वाहन के उपयोग के लिए होगा न कि एक भाग के लिए उसके बाद।
- (13) बसों की नियुक्ति बस कोड अखिल भारतीय मानक (एआईएस) 052 के अनुसार अपने बेड़े (मिनी / मिडी / मानक आकार) में बसों के आकार को तय करने के लिए सीमित लाइसेंस धारक की स्वतंत्रता पर होगी।

4. लाइसेंस देने/नवीनीकरण की प्रक्रिया:

- (1) कोई भी व्यक्ति इस योजना के संलग्न प्रपत्र 1 में लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ भुगतान के प्रमाण और इस योजना के खंड-5 में उल्लिखित सुरक्षा जमा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है:-
 - (क) वैध परमिट की एक सच्ची प्रति के साथ संलग्न होने का प्रस्ताव करने वाले सभी वाहनों की सूची।
 - (ख) सभी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध होने का प्रमाण।
 - (ग) लीज समझौते में एक बार में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस धारक के पक्ष में ऐसे वाहनों के प्रभावी नियंत्रण और कब्जे के हस्तांतरण का विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।
 - (घ) प्रत्येक बस के पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा की प्रति।
 - (ङ) वाहन की फिटनेस जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बस में सीसीटीवी और अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं ठीक से स्थापित हैं।
 - (च) संचालन को विनियमित करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के संबंध में गैर-न्यायिक स्टांप पेपर में अंडरटेकिंग और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय-VIII और XIII के प्रावधानों के दायरे में लाने के लिए दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के अध्याय-VIII के अनुसार अनुबंध कैरिज परमिट का कब्जा आवश्यक है।
- (2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, पावती ऑनलाइन जारी की जाएगी।
- (3) सक्षम प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि सभी आवश्यक आवश्यकताएं और दस्तावेज सही पाए गए हैं, या तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस प्रदान करेगा या किसी विसंगति के मामले में इस संबंध में पूर्ति के लिए आवेदक को जानकारी देगा।
- (4) लाइसेंस प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (5) लाइसेंस पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (6) लाइसेंस का नवीनीकरण स्वचालित नहीं है और लाइसेंस धारक के अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है और यह योजना के संतोषजनक अनुपालन और सुरक्षा रिकॉर्ड, उपभोक्ता संतुष्टि और सेवा की समग्र गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए होगा। लाइसेंस धारक, किसी अन्य पैरामीटर (एस) के साथ जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना जा सकता है।
- (7) लाइसेंस धारक को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रवर्तन शाखा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से क्लॉज-5 चालान निकासी प्रमाण पत्र में उल्लिखित शुल्क के साथ संलग्न फॉर्म 1 में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (8) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले किया जाएगा। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी अंतिम तिथि के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है, अगर यह संतुष्ट है कि आवेदक को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था, जो योजना के खंड 10 (4) में निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन है।
- (9) लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

5. शुल्क और सुरक्षा जमा:

- (1) लाइसेंस देने के लिए नीचे उल्लिखित शुल्क और सुरक्षा जमा के साथ आवेदनों पर विचार किया जाएगा:

(क) लाइसेंस के लिए शुल्क:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1	लाइसेंस का अनुदान	5,00,000
2	लाइसेंस का नवीनीकरण	2,500

3	डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना	2,500
4	अनुज्ञप्तिधारी के पते में परिवर्तन की सूचना हेतु	2,500

(ख) लाइसेंस के लिए सुरक्षा जमा:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1	100 बसों तक	1,00,000
2	1000 बसों तक	2,50,000
3	1000 से अधिक बसें	5,00,000

(2) स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(3) बस कतार आश्रयों के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त स्टैंड शुल्क का भुगतान परिवहन विभाग, जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

6. किराया और टिकटिंग:

(1) लाइसेंस धारक किसी भी मार्ग/गंतव्य के लिए उपयुक्त किराया संरचना निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। किराया आम जनता की जानकारी के लिए मोबाइल और वेब आधारित एप्लिकेशन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) डायनेमिक प्राइसिंग की अनुमति होगी, बशर्ते कि बेस फेयर डीटीसी एसी बसों के पीक फेयर से कम न हो।

(3) लाइसेंस धारक यात्रियों को केवल मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन सुविधा के माध्यम से संलग्न करेगा और कोई भौतिक टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

(4) यात्रियों से शुल्क केवल इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल भुगतान माध्यम से वसूल किया जाएगा।

7. लाइसेंस धारक के दायित्व:

(1) लाइसेंस धारक इस योजना के तहत लगाए गए प्रत्येक वाहन के लिए और उसके संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात्:

- (क) लाइसेंस धारक, वाहन की प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले, अपने मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर, ऐसी यात्रा का मार्ग, वाहन, प्रीमियम बस चालक और/या अन्य कर्मचारियों और एक का विवरण देगा। उस यात्रा के लिए यात्री प्रकट। यात्रा के किसी भी पड़ाव से यात्रियों की आगे की बुकिंग निष्पादित की जा सकती है और यात्री सूची में शामिल की जा सकती है, बशर्ते ऐसी बुकिंग बोर्डिंग समय से कम से कम 10 मिनट पहले की जाए। बशर्ते आगे, कि मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर प्रदर्शित यात्री मेनिफेस्ट यात्रियों के नामों का खुलासा नहीं करेगा और केवल उनके अंतिम नाम, आयु और लिंग का वर्णन करेगा, जैसा भी मामला हो;
- (ख) कोई भी लाइसेंस बिंदु (क) के प्रावधान के संबंध में ऐसे वाहन में किसी भी व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि उनका नाम यात्री सूची में शामिल न हो।
- (ग) लाइसेंस धारक शिकायत दर्ज करने की सुविधा के उद्देश्य से अपने मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर एक सुविधा शामिल करेगा, यदि कोई हो। इसके अलावा लाइसेंस धारक बस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएगा जिसमें लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त तंत्र पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जानकारी होगी। लाइसेंस धारक मासिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण के साथ शिकायत का सारांश प्रस्तुत करेगा;
- (घ) लाइसेंस धारक महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा और महिला यात्रियों द्वारा शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए अपने मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन सहित एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करेगा;
- (ङ) लाइसेंस धारक किसी यात्री से किराया शुल्क स्वीकार करने के बाद किसी भी यात्रा को रद्द नहीं करेगा, सिवाय इसके कि कोई अप्रत्याशित घटना हो, जिसके बाद वह एक वैकल्पिक वाहन प्रदान करने या यात्रियों द्वारा भुगतान किए गए किराए को तुरंत वापस करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ;

- (च) खराब होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से वैकल्पिक वाहन प्रदान करने में विफल रहने पर लाइसेंस धारक, सिवाय अप्रत्याशित घटना के, वह तत्काल धनवापसी करेगा जो प्रत्येक से प्राप्त राशि के बराबर होगी। प्रभावित यात्रियों और पूर्व-निर्धारित परिसमापन हर्जाने के माध्यम से उसके आधे के बराबर राशि, और लाइसेंस धारक की प्रत्येक यात्री के लिए और प्रत्येक यात्री के संबंध में ऐसा भुगतान करने में विफलता के कारण उसे खंड 11 के तहत जुर्माना के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। ;
- (छ) चालक की तस्वीर, लाइसेंस संख्या, यात्री सेवा वाहन बैज संख्या और वाहन के पंजीकरण चिह्न के साथ-साथ परिवहन हेल्पलाइन नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर का विवरण बस के अंदर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि यह यात्रि को सीधे दिखाई दे।
- (ज) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अखिल भारतीय मानक (एआईएस) 052 (बस कोड), अखिल भारतीय मानक (एआईएस) 140 (वाहन ट्रेकिंग प्रणाली, कैमरा निगरानी प्रणाली, और आपातकालीन अनुरोध) का अनुपालन करने वाली प्रीमियम वातानुकूलित बसें बटन) और अखिल भारतीय मानक 153 मानक (फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (FDAS) परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अन्य विशिष्टताओं के साथ बेड़े में शामिल किए जाएंगे। एग्रीगेटर अपने बेड़े में बसों के आकार को (मिनी / मिडी / मानक आकार) बस कोड अखिल भारतीय मानक (एआईएस) 052 के अनुसार तय करने के लिए स्वतंत्र होगा
- (झ) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यात्रा के दौरान यात्रियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक वाहन में कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए और जिसकी रिकॉर्डिंग लाइसेंस धारक द्वारा कम से कम पंद्रह दिनों के लिए संग्रहीत की जाएगी। प्रत्येक यात्रा की तारीख और किसी भी कानून लागू करने वाली एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना;
- (ञ) बसों/रूटों की खोज, बुकिंग सवारी और डिजिटल भुगतान करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा तैनात वर्तमान डिजिटल समाधान **वन दिल्ली ऐप** के साथ प्रस्तावित सेवा का लिंक प्रदान करने के लिए लाइसेंस धारक जिम्मेदार होगा।
- (ट) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि मोटर वाहन अधिनियम -1988 के अध्याय-XI अधिनियम के प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए वाहन में रहने वालों (चालक और कंडक्टर सहित) के लिए वाहन को बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना चाहिए जो कम से कम 10 लाख रुपये का आकस्मिक कवरेज प्रदान करेगा।
- (ठ) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के तहत तैनात प्रत्येक वाहन के पास हर समय केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 62 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-56 के तहत फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र होगा।
- (ड) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वैध वैधता वाले अग्निशामक प्रत्येक बस में स्थापित किए जाएंगे और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाएंगे;
- (ढ) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि संचालित करने के लिए योजना के तहत तैनात प्रत्येक बस के पास दिल्ली मोटर वाहन नियम-1993 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियम 35 के तहत एक वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा;
- (ण) लाइसेंस यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित अनुसार से अधिक नहीं होगी;
- (त) लाइसेंस धारक एक यात्री वाहन के उपयोग के संबंध में सभी लागू शर्तों का पालन करेगा जैसा कि अनुबंध कैरिज बसों के मामले में होता है और इसके किसी भी उल्लंघन को प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। अध्याय-VIII: मोटर वाहन अधिनियम -1988 के यातायात का नियंत्रण और उसके तहत बनाए गए नियम और दिल्ली मोटर वाहन नियम -1993 में निर्धारित विभिन्न प्रावधान;
- (थ) लाइसेंस धारक जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन के चालक के पास सार्वजनिक सेवा वाहन बैज के साथ बस चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी होनी चाहिए।

- (द) लाइसेंस धारक जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह लगे चालक मोटर वाहन अधिनियम - 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों और दिल्ली मोटर वाहन नियम -1993 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक प्रावधानों का पालन करेंगे। आगे वाहन चालक के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध धारा-53, 54 एवं 55 के प्रावधानों के तहत अपराध करने की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी। मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा-19 के तहत चालक का लाइसेंस रद्द करना।
- (ध) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्सर्जन मानदंड सीएनजी वाली बसों का अधिग्रहण योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल पुराना नहीं होगा। इसके बाद किसी भी नई बस को शामिल करना, प्रचलित उत्सर्जन मानदंड, BS-VI का अनुपालन करना चाहिए, या तो वातानुकूलित CNG/इलेक्ट्रिक बसें। 1 जनवरी, 2024 के बाद केवल इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, इस योजना के तहत बीएस-VI अनुपालन होने पर भी सीएनजी संचालित बसों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (न) लाइसेंस धारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केंद्रीय अधिनियम 21) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- (त) लाइसेंस धारक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित तंत्र को सुनिश्चित करेगा और विशाखा दिशा-निर्देशों के तहत महिला कर्मचारियों की शिकायत को दूर करने के लिए समिति के गठन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
- (प) लाइसेंस धारक एनसीआर क्षेत्र में अपनी सभी बसों के लिए पर्याप्त रात भर की पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर सड़कों, गलियों आदि सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. डीटीसी बस कतार आश्रयों का उपयोग:

- (1) अनुज्ञप्तिधारी एवं चालक को अधिसूचित बस क्यू शेल्टरों पर ही यात्रियों को चढ़ाना एवं उतारना होगा। बस क्यू शेल्टरों के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीधे दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को अलग से किया जाएगा।
- (2) दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से किसी भी अतिरिक्त हॉल्टिंग स्टेशनों का अनुरोध किया जाएगा।

9. ब्रांडिंग और विज्ञापन:

- (1) इस योजना के तहत शामिल की जाने वाली सभी प्रीमियम बसें एक समान रंग और लोगो का पालन करेंगी जैसा कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (2) लाइसेंस धारक को लागू कानूनों के अनुपालन में गैर-वाणिज्यिक आधार पर बसों के अंदर विज्ञापन देने का अधिकार होगा ताकि प्रीमियम बस योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी को संबंधित प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए परिनियोजित बसों के भीतर विज्ञापन स्थान बेचने का अधिकार होगा।
- (4) किसी भी परिस्थिति में इसे लाइसेंस धारक द्वारा सरकारी उपक्रम होने के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा।

10. शर्तों/दायित्वों के उल्लंघन के लिए दंड:

- (1) दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 में निर्धारित किसी भी दायित्व या शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) यह योजना अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुपालन और दंड के अलावा लागू / लागू करने योग्य होगी और अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ी जाएगी।

- (3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर योजनान्तर्गत आवश्यक न्यूनतम संख्या में बसों के संचालन/अनुरक्षण में विफल रहने की स्थिति में सुनवाई का उचित अवसर देते हुए जमा की गई समस्त जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (4) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से नब्बे दिन पहले होगी। उदाहरण के लिए, यदि नियत तारीख तक आवेदन जमा नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित विलंब शुल्क देय होगा:-

लाइसेंस की समाप्ति के बाद	लाइसेंस की समाप्ति तक
1000/- (एक हजार मात्र) रु.	रु. एक हजार से अधिक रु. 100/- प्रति दिन

- (5) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय VIII और अध्याय XIII और दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के अध्याय-VIII और मोटर-वाहन-ड्राइविंग-विनियमन अधिनियम 2017 के प्रावधान इस योजना और कार्रवाई के तहत संचालित वाहनों पर लागू होंगे। जैसा निर्धारित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

11. जुर्माने की वसूली:

जुर्माना लगाने और नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस धारक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।

12. लाइसेंस का निलंबन और रद्दीकरण:

(1) लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी 6 महीने से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस को निलंबित कर सकता है, यदि यह राय है कि-

- (क) लाइसेंस धारक से जुड़ी कोई भी बस, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी अनुपालन के डिफॉल्ट में है;
- (ख) किसी भी बस को लेन ड्राइविंग की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, तेज गति और रैश ड्राइविंग में पाया जाता है।
- (ग) लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में बस को बनाए रखने में विफल रहा है; या इस योजना के प्रावधान के साथ; या खंड -7 में उल्लिखित दायित्वों।
- (घ) कोई भी बस चालक महिलाओं/विकलांगों/वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप के साथ किसी भी दुर्व्यवहार या दुराचार का दोषी पाया जाता है।

(2) जहां कोई परमिट रद्द या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी है और यदि परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी, परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय, लाइसेंस धारक से सुरक्षा जमा के आधे के बराबर राशि की वसूली कर सकता है। जो कि धारा 5(बी) में वर्णित सुरक्षा राशि जमा कर लाइसेंस धारक द्वारा लगायी गयी बसों की संख्या के संबंध में परिवर्तन।

13. अपील:

(1) सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता प्राधिकरण के आदेश पर आपत्तियों के आधार को निर्धारित करते हुए एक ज्ञापन के रूप में एक अपील को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में निर्दिष्ट 500 / - रुपये की फीस के साथ होगा। पंजीकरण प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील के लिए भुगतान की जाने वाली फीस के बराबर होगा।

(3) अपीलकर्ता प्राधिकारी, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और ऐसी जांच के बाद उचित आदेश पारित कर सकता है।

14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की शक्तियां और उत्तरदायित्व।

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को एग्जीगेटर से ऐसी जानकारी और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा, जैसा कि एग्जीगेटर द्वारा पूर्व लिखित सूचना के अनुसार योजना के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के पास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के फॉर्म 1 में निर्दिष्ट एग्रीगेटर के परिसर की खोज और जांच करने की शक्ति होगी;
- (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वाहन और सारथी पोर्टल तक पहुंच प्रदान करेगी ताकि एग्रीगेटर को ऐप के साथ एकीकृत वाहनों और ड्राइवरों के विवरण को अपडेट करने में सक्षम बनाया जा सके।
- (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार खंड 14(1) के तहत एग्रीगेटर से प्राप्त दस्तावेजों और सूचनाओं की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आशीष कुंद्रा, प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त

फॉर्म 1

[खंड 4 देखें]

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

मैं, अधोहस्ताक्षरी, दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रीमियम बसों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करता हूँ:

1	संस्था/पंजीकृत कंपनी/साझेदारी/एलएलपी/कंसोर्टियम का नाम	
2	आवेदक की प्रकृति ● पंजीकृत कंपनी ● साझेदारी ● एलएलपी ● सहकारी समिति ● कंसोर्टियम ● अन्य	
3	निगमन की तिथि:	
4	मुख्य कार्यालय का पता	
5	शाखाओं की संख्या और पते, यदि कोई हो	
6	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण (क) पूरा नाम: पुत्र/पुत्री/पत्नी:	

	(ख) पता: (ग) दूरभाष सं.	
7	प्रति दिन यात्री यात्राओं की औसत संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष में):	
8	औसत वार्षिक कारोबार (पिछले 3 वित्तीय वर्षों में):	
9	संचालित की जाने वाली बसों की संख्या (दस्तावेज सहित) और इसका आकार (मानक/मिडी/मिनी)	
10	बुकिंग, रूटिंग और टिकटिंग के लिए डिजिटल इंटरफ़ेस का प्रमाण।	
11	लाइसेंस का विवरण, यदि पहले से धारित है:	
12	विवरण शुल्क भुगतान	
13	आयुक्त परिवहन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार के पक्ष में बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षा जमा का विवरण।	

घोषणा:

- मैं प्रीमियम बसों को एकत्र करने के लिए व्यवसाय करने की शर्तों से परिचित हूँ।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही और सत्य हैं।
- वाहनों और ड्राइवरों की सूची उनके संबंधित लाइसेंस और बैज की एक सच्ची प्रति के साथ संलग्न है।
- लाइसेंस प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

जगह.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर /

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए चेकलिस्ट:

1. निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति:
2. लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा के भुगतान का प्रमाण
3. अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रमाण
4. वाहनों की सूची उनके लाइसेंस की सत्य प्रति के साथ
5. ड्राइवरों की सूची उनके लाइसेंस और बैज की एक सच्ची प्रति के साथ
6. सभी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध होने का प्रमाण
7. कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की कॉपी (इलेक्ट्रिक बसों के अलावा)

फॉर्म 2

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत प्रीमियम बसें के एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस

ऑपरेटर/लाइसेंस का नाम:

आवेदक का नाम:

पुत्र/पत्नी/पुत्री:

व्यवसाय के स्थान का पूरा पता:

मुख्य कार्यालय

शाखा कार्यालय

प्रीमियम बसें के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है।

यह लाइसेंस को जारी किया जाता है। और तक वैध है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

नवीनीकरण

..... से तक
नवीनीकृत

राज्य परिवहन प्राधिकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार के प्रमुख सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, परिवहन विभाग

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th May, 2023

F. No F(12)/Policy/AS/STA/2016/49928.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (3) of Section 67 read with Section 93 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 and in pursuance and compliance of the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2020 issued vide Notification No. S.O.4251 (E) dated 26th Nov, 2020 of Ministry of Road, Transport and Highways, Government of India, the Lieutenant Governor of National Capital territory of Delhi hereby publish the draft scheme namely, ‘**The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023**’ for information to all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft scheme will be taken into consideration on or after expiry of 30 days from the date of its publication in Delhi Gazette.

Objections or suggestions in this regard shall be addressed to the Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi -110054 or on email at commpt@nic.in or tpassta@gmail.com.

DRAFT SCHEME:**1. Short title, application and commencement:**

- It shall be called the “**The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023**”.
- It shall, apply to all premium buses operated under a valid Aggregator license granted by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, to operate within the National Capital Territory of Delhi.
- It shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions:

(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:

- (a) “**Act**” means the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988):
- (b) “**Appellate Authority**” means Secretary, State Transport Authority, Department of Transport, Government of National Capital Territory of Delhi, for the purpose of entertaining appeal in respect of grant and renewal of license under the said scheme;
- (c) “**App**” means an electronic interface operated by the License holder or any third party on behalf of the License holder which may be accessed either through a computer resource or a communication device;
- (d) “**Competent Authority**” means the Deputy Secretary, State Transport Authority, Department of Transport, Government of National Capital Territory of Delhi shall grant/renew/suspend/cancel the license, under the provisions of said scheme;
- (e) “**License Holder**” means a person or entity that holds a license for operation of buses under this scheme as issued by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (f) “**Passenger Manifest**” means a digital record of persons who are likely to travel in a premium bus during the course of a trip and on whose behalf the license holder enters into a contract, express or implied, with the owner of bus, or any person authorized by him for hiring a vehicle as a whole in accordance with this scheme;
- (g) “**Permit**” means a valid contract carriage permit issued by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi under Section-74 of Motor Vehicle Act-1988;
- (h) “**Premium Bus**” means a luxury public service vehicle having seating capacity of more than 12 passengers with the following features:
Air Conditioner, Wi-Fi, GPS, CCTV, Panic Button, 2 x 2 seats, reclining seats or any other specification / feature as incorporated in the scheme from time to time.
Any other specifications / conditions as deemed fit under the constrained circumstances will be incorporated time to time by the Transport Department;
- (i) “**Stand Fee**” means the fee, as prescribed by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi for using bus queue shelters to pick up and drop passengers;

2) Words and expressions used in this scheme, but not defined herein, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Eligibility for grant of aggregator license:

- (1) License holder shall operate and maintain a fleet of minimum 50 premium buses, to be made operational within 90 days from the day of grant of license.
- (2) The requirement for minimum and maximum number of premium buses may be modified by the Competent Authority from time to time, if need arises.
- (3) The license holder may, for and on behalf of the passengers, determine potential routes on which the vehicles operated by it shall ply.

Provided that the self-determined potential routes may not be objected by the Traffic Police being the agency authorized to control the Traffic or any other Local Bodies controlling and maintaining the route, if object, the self-determined routes shall stand terminated.

- (4) The details of such routes shall be notified on the mobile or web-based application for information to the general public.
- (5) No modification/ termination of any route on which the bus is operated shall not be changed by license holder in any case without intimation to the Competent Authority after giving a notice of seven days in advance. The effect of the change of route shall also be informed to the general public by the license holder, through mobile or web-based application.
- (6) No such route shall be terminated by the license holder, if an advance booking/confirmation is made for that route provided in case of any exigency to terminate the service the booking amount if obtained in advance shall be returned on the same day to the commuter.

- (7) The license shall not be granted to any firm or entity either insolvent, or a blacklisted by any State Transport Authority or Regional Transport Authority of any State or Union Territory of India.
- (8) The license holder shall have the corporate or branch office within National Capital Region (NCR) managed by duly authorized representative under intimation to Competent Authority.
- (9) The license holder at the time of applying for the license under this scheme shall have the mandatory experience for at least 03 years for operating/managing/ the vehicles in public transport/shared transportation along with following mandatory requirements:-
 - (a) a fleet of minimum 100 passenger buses during the last three financial years (each year); or
 - (b) a fleet of minimum 1000 passenger cars during the last three financial years (each year); or
 - (c) In case of a mixed fleet of passenger cars and buses, the total minimum fleet must be equal to at least 100 buses. For this purpose, 10 cars would be deemed to be equal to 1 bus.
- (10) The license holder shall comply with all the applicable provisions prescribed under the Act and Rules framed thereunder either as Central Motor Vehicle Rules-1989 or The Delhi Motor Vehicle Rules -1993 or of the Information Technology Act, 2000 by submitting an undertaking on non-judicial stamp paper along with the request for issuance of license under this scheme.
- (11) The License holder shall possess a Contract Carriage permit in order to regulate the operation and to maintain the discipline on road and in the provisions of Chapter-VIII & XIII of Motor Vehicle Act-1988 read with Chapter-VIII of Delhi Motor Vehicle Rules-1993, shall be applicable on them.
- (12) The License holder shall entered into a contract with a permit holder for use of the vehicle of such permit holder in accordance with the provisions of this scheme and such contract shall be for use of the vehicle as a whole and not for a part thereof.
- (13) The engagement of the buses shall be at the liberty of the license holder confined to decide the size of the buses in its fleet (Mini / Midi / Standard Size) as per Bus Code All India Standard (AIS) 052.

4. Procedure for grant/renewal of the license:

- (1) Any person may make an application for grant of license in the Form 1 appended to this scheme, accompanied by proof of payment with prescribed fee and security deposit as mentioned in Clause- 5 of this scheme, along with following documents:-
 - (a) List of all vehicles that propose to engage along with a true copy of valid permit.
 - (b) Proof of adequate parking spaces available for all the vehicles.
 - (c) The lease agreement must contain specific provision of transfer of effective control and possession of such vehicles in favor of the license holder for a term, at least one year, at a time.
 - (d) Copy of Registration Certificate and Insurance of each bus.
 - (e) Fitness of the vehicle indicating therein that the CCTV and other mandatory requirements are properly installed in the bus.
 - (f) Undertaking in non-judicial stamp paper with regard to regulate the operation and to maintain the discipline on road and to bring within the ambit of provisions of Chapter-VIII & XIII of Motor Vehicle Act 1988 read with Chapter-VIII of The Delhi Motor Vehicle Rules 1993, the possession of the Contract Carriage permit is required.
- (2) Upon receipt of such application, the acknowledgement shall be issued online.
- (3) The Competent Authority after satisfying himself that all the necessary requirements and documents found in order, shall either grant the license within a period of thirty days from the date of receipt of application or in case of any discrepancy the information in this regard shall be conveyed to the applicant for fulfillment.
- (4) No application for grant/renewal of license shall be rejected without giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant.
- (5) The licence shall be valid for a period of five years.
- (6) The renewal of the license is not automatic and not available as a matter of right of the license holder and would be subject to satisfactory compliances with the Scheme and taking into account the safety records, consumer satisfaction, and overall quality of service of the license

holder, along with any other parameter(s) that may be considered relevant by the Competent Authority.

- (7) The license holder shall submit an application for renewal of the licence in Form 1 appended with the fee as mentioned in the Clause-5 challan clearance certificate from Enforcement Branch and Delhi Traffic Police.
- (8) The application for renewal of license shall be made not less than 90 days before the date of its expiry. However, Competent Authority may entertain and application for the renewal of the license after the last date, if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making an application within the time specified, subject to payment of fees as prescribed in clause 10 (4) of the Scheme.
- (9) The license shall be renewed for a period of five years from the date of expiry of the license.

5. Fee & Security Deposit:

- (1) The applications accompanied with the Fee and Security Deposit as mentioned below shall be considered for granting the license:

(a) Fee for license:

S. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	Grant of license	5,00,000
2.	Renewal of license	2,500
3.	Issue of duplicate license	2,500
4.	For noting change of Address of the licensee	2,500

(b) Security Deposit for license:

S. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	Upto 100 buses	1,00,000
2.	Upto 1000 buses	2,50,000
3.	More than 1000 buses	5,00,000

- (2) No license fee shall be levied on electric buses to promote the clean transport options.
- (3) An additional stand fee for use of bus queue shelters shall be paid as notified from time to time by the Transport Department, GNCTD.

6. Fare and Ticketing:

- (1) The license holder shall be at liberty to prescribe a suitable fare structure for any route/ destination. The fare shall be displayed on the mobile and web-based application for the information of the general public.
- (2) Dynamic pricing shall be permissible provided that the base fare shall not be less than the peak fare of DTC AC buses.
- (3) The license holder shall engage passengers only through mobile and web-based application facility and no physical tickets shall be issued.
- (4) The charges from the passengers shall be collected only through electronic/ digital payment mode.

7. Obligations of license holder:

- (1) The license holder shall be responsible for complying with the following conditions for and in respect of every vehicle deployed under this scheme, namely:
 - (a) The license holder shall, prior to commencement of each trip of a vehicle, convey on its mobile and web-based application, the route of such trip, the particulars of the vehicle, premium bus driver and/or other staff and a passenger manifest for that trip. Further booking of passengers from any stop in the trip may be executed and included in the passenger manifest provided such booking shall be executed at least 10 minutes before the boarding time. Provided further, that the passenger manifest displayed on the mobile and web-based application shall not disclose the names of the passengers and shall only describe their last name, age and gender, as the case may be;
 - (b) License holder shall not allow any person in such a vehicle on any trip with respect to

provision of Clause-(a), unless their name is included in the passenger manifest.

- (c) The license holder shall incorporate a feature on its mobile and web-based application for the purpose of facilitating to lodge complaint if any. Further the license holder shall also affix an electronic display board inside the bus wherein the information with regard to lodging complaint on the mechanism derived by the license holder. The license holder shall submit a summary of complaint along with clarification/explanation to the Competent Authority on monthly basis;
- (d) The license holder shall take measures to ensure the safety and security of women passengers and shall provide a rapid response mechanism, including a panic button on its mobile and web-based application, for prompt redressal of complaints by women passengers;
- (e) The license holder shall not cancel any trip after accepting the hire charges from a passenger, save and except upon occurrence of a force majeure, whereupon it shall make best endeavors to provide an alternative vehicle or to refund the fare paid by passengers forthwith;
- (f) The license holder upon failure to provide an alternative vehicle in case of a break-down or for any other reason, save and except force majeure, he shall make a refund forthwith which shall be equal to the amount received from each of the affected passengers and an amount equal to one half thereof by way of pre-determined liquidated damages, and each failure of the license holder to make such payment for and in respect of each passenger shall make him liable to payment of a fine under Clause 11 thereof;
- (g) The details containing the photograph of the driver, license number, Passenger Service Vehicle Badge number and registration mark of the vehicle, along with Transport Helpline number and Police Helpline number shall be displayed prominently inside the bus such that it is directly visible to the passengers.
- (h) The license holder shall ensure that only premium air-conditioned buses having compliance of with All India Standard (AIS) 052 (Bus Code), All India Standard (AIS) 140 (vehicle tracking system, camera surveillance system, and emergency request button) and All India Standard 153 standards (Fire Detection and Alarm System (FDAS) with other specifications as prescribed by the Transport department shall be inducted into the fleet. The aggregator shall be at liberty to decide the size of the buses in its fleet (Mini / Midi / Standard Size) as per Bus Code All India Standard (AIS) 052;
- (i) The license holder shall ensure that there shall be at least two CCTV cameras must be installed in each vehicle for recording the movements of passengers during each trip and recording of which shall be stored by the license holder for at least fifteen days from the date of each trip and produce the same on demand by any law enforcing agency;
- (j) The license holder shall be responsible for providing a link of the proposed service with the current digital solution ONE DELHI app deployed by Transport Department, for discovering buses/routes, booking rides and making digital payments.
- (k) The license holder shall ensure that the vehicle must be covered by a policy of insurance which shall provide accidental coverage of not less Rs. 10 lakhs for the occupants of the vehicle (including driver and conductor) to facilitate the provisions as stipulate in Chapter-XI of Motor Vehicle Act-1988;
- (l) The license holder shall ensure that each and every vehicle deployed under the scheme shall possess, at all times, a valid certificate of fitness under Section-56 of Motor Vehicle Act-1988 read with Rule 62 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;
- (m) The license holder shall ensure that the fire extinguisher having valid validity shall be installed in each bus and carry first aid kit as stipulate under the provisions Central Motor Vehicles Rules, 1989;
- (n) The license holder shall ensure that each bus deployed under the scheme to operate shall possess and carry a valid pollution certificate under rule 35 of NCT of The Delhi Motor Vehicle Rules-1993;
- (o) The license shall ensure that number of passengers shall not exceed over and above as mentioned in registration certificate duly granted by the registering authority;
- (p) The license holder shall comply with all applicable conditions in respect of the use of a passenger vehicle as in the case of Contract Carriage buses and any violation thereof shall be treated as violation for the purpose of taking appropriate action by Enforcement Agencies under the Chapter-VIII : Control of Traffic of Motor Vehicle Act-1988 and Rules framed thereunder and the various provisions as stipulate in The Delhi Motor Vehicle Rules-1993;

- (q) The license holder as the case may be, shall ensure that the driver of the vehicle must possess the category of the driving license required to operate a bus along with Public Service Vehicle Badge.
- (r) The license holder as the case may be shall ensure that the driver so engaged shall comply all the necessary provision referred to in Motor Vehicle Act-1988 and Rules framed thereunder and The Delhi Motor Vehicle Rules-1993. Further any act of criminal offence if found against the driver of the vehicle, the action against the license holder shall be taken under the provisions of Section-53, 54 & 55 in view of the gravity of the commission of offence in addition to process of revocation of license of the driver under Section-19 of Motor Vehicle Act-1988.
- (s) The license holder shall ensure that the acquisition of buses having emission norms CNG shall not be three years old from the date of notification of the scheme. Subsequently induction of any new bus, the prevailing emission norms, BS-VI must be compliant, either Air-Conditioned CNG / electric buses. After January 1, 2024 the induction of electric buses only shall be allowed, no CNG operated bus even if having BS-VI compliance shall not be allowed to induct under this scheme.
- (t) The license holder shall comply with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) and the rules and regulations made thereunder.
- (u) The license holder shall ensure stipulated mechanism for protecting the rights of women employees as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and also ensure to compliance the order of the Hon'ble Supreme Court with regard to constitution of committee to address the women employees complaint under VISHAKHA guidelines.
- (v) The license holder shall ensure availability of adequate overnight parking space for all its buses in NCR region, under no circumstances, parking on any public space including roads, streets, etc., within National Capital Territory of Delhi would be allowed.

8. Use of DTC Bus Queue Shelters:

- (1) The license holder and driver shall have to pick up and drop passengers at the notified bus queue shelters only. The fee for usage of bus queue shelters shall be paid separately to Delhi Transport Infrastructure Development Company Ltd. directly.
- (2) Any additional halting stations shall be requested through a single window mechanism established by the Delhi Transport Infrastructure Development Company Ltd.

9. Branding and advertising:

- (1) All premium buses inducted under this scheme shall follow a uniform color and logo as prescribed by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
- (2) The license holder shall have the right to advertise inside the buses, on a non-commercial basis, in compliance with applicable laws so as to create awareness about the premium bus scheme.
- (3) The license holder shall have the right to sell advertising space inside the deployed buses to earn additional revenue, after obtaining the approval of concerned authorities.
- (4) Under no circumstances it shall be proclaimed by license holder as being Govt. undertaking.

10. Penalty for Violation of conditions/obligations:

- (1) In the event of any violation of any obligations or conditions prescribed in **The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023**, the license holder shall be liable for penalty in accordance with the provisions of Section 193 of the Motor Vehicle Act 1988.
- (2) This scheme shall be applicable/enforceable in addition to the compliances and penalties provided under the Act and shall be read in conjunction with the existing provisions of the Act & Rules made thereunder.
- (3) In case of failure to operate/maintain, the minimum number of buses required under the scheme within 90 days from the date of grant of license, the entire security deposited shall be forfeited after giving reasonable opportunity of being heard.
- (4) The last date for submitting application for renewal of license shall be Ninety days prior to the date of expiry of the license. In instance if the application is not submitted by the due date, the following late fee shall be payable:

Upto the expiry of the license	After expiry of the license
Rs. 1000/- (One Thousand only)	Rs. One Thousand plus Rs. 100/- per day

- (5) The provisions of Chapter VIII & Chapter XIII of Motor Vehicle Act 1988 and Chapter-VIII of The Delhi Motor Vehicles Rules 1993 and Motor-Vehicle-Driving-Regulation Act 2017 shall be applicable to the vehicles operated, under this scheme and action as prescribed shall be initiated against them.

11. Recovery of Penalty:

In case of failure of payment of fine within a period of fifteen days from the date of imposition and notice, the Competent Authority may, suspend or cancel the licence after providing a reasonable opportunity of being heard to the License holder.

12. Suspension and cancellation of license:

- (1) The competent authority may suspend the license for a specified period not exceeding 6 months, after giving the license holder an opportunity of being heard, if it is of the opinion that-
- Any bus associated with the license holder, is in default of legal compliances under the Motor Vehicle Act 1988 ;
 - Any bus is found to be in violation of lane driving conditions, over speeding and rash driving.
 - The license holder has failed to maintain the bus in compliance with the provisions of the Motor Vehicles Act 1988 and or Rules framed thereunder; or with the provision of this scheme; or the obligations as enumerated in Clause-7.
 - Any bus driver is found to be guilty of any misbehavior or misconduct with women/handicapped/sr. citizens specifically or any other commuter.
- (2) Where a permit is liable to be cancelled or suspended and if circumstances so arise, the competent authority may, instead of cancelling or suspending the permit, recover from the license holder an amount equivalent to one half of the security deposit that may be varied with respect to the number of buses engaged by the license holder by depositing the security money as mentioned in clause 5(b).

13. Appeal:

- Any person aggrieved by any order of the Competent Authority may within thirty days of the receipt of the order, make an appeal to the Appellant Authority.
- An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth the grounds of objections to the order of the Appellant Authority and shall be accompanied by fees of Rs 500/- as specified in The Delhi Motor Vehicle Rules 1993 at par with the fee to be paid for appeal against the order of Registering Authority.
- The Appellant Authority may, after giving a reasonable opportunity of hearing to the parties and after such enquiry as it may deem fit pass an appropriate order.

14. Powers & Responsibilities of Government of National Capital Territory of Delhi.

- The Government of National Capital Territory of Delhi shall be empowered to call for such information and documents from the Aggregator, as deemed fit to ensure compliance by the Aggregator with the Scheme pursuant to prior written notice.
- The Government of National Capital Territory of Delhi shall have the power to conduct search and investigation of the Aggregator's premises, as specified in Form 1 of the Scheme, for the effective implementation of the Scheme;
- The Government of National Capital Territory of Delhi shall provide access to the VAHAN and SARATHI portal operated by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India to enable the Aggregator to update the details of vehicles and Drivers integrated with the App.
- The Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure complete confidentiality and secrecy of the documents and information obtained from the Aggregator under Clause 14(1) and any such other information which it may call for.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUNDRA, Pr. Secy.-Cum-Commissioner

FORM 1**[See Clause 4]**

Application for grant or renewal of licence for Aggregator under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregators (Premium Buses) Scheme, 2023

To

Secretary,

The State Transport Authority

Govt. of NCT of Delhi

I, the undersigned, hereby apply for granting a licence for operation as an Aggregator for premium buses in NCT of Delhi under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023:

1.	Name of Entity/ Registered Company/ Partnership/ LLP/ Consortium	
2.	Nature of Applicant <ul style="list-style-type: none"> ● Registered Company ● Partnership ● LLP ● Cooperative Society ● Consortium ● Other 	
3.	Date of Incorporation:	
4.	Address of the main office	
5.	Number of branches and addresses, if any	
6.	Particulars of the Authorized Signatory <p>(a) Full Name: Son/Daughter/Wife of:</p> <p>(b) Address:</p> <p>(c) Telephone No.</p>	
7.	Average number of passenger trips per day (in the last Financial Year):	
8.	Average Annual Turnover (in the Last 3 Financial Years):	
9.	Number of buses (along with documentation) to be operated and its size (Standard/Midi/ Mini)	
10.	Proof of a digital interface for booking, routing and ticketing.	
11.	Particulars of Licence, if already held:	
12.	Details Fee Paid	
13.	Details of Security Deposit by way of Bank Guarantee in favour of Commissioner Transport, Govt. of NCT Of Delhi.	

Declaration:

- I am conversant with the conditions for carrying the business for aggregating premium buses.
- I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are correct and true.
- List of vehicles and drivers along with a true copy of their respective licenses and badges are attached herewith.

- The prescribed license fee for grant/ renewal of licence has been paid.

Place.....

Date

Signature of Applicant/

Authorized Signatory

(Alongwith company seal, as applicable)

Checklist for Documents to be submitted:

1. Copy of certificate of Incorporation/ Registration:
2. Proof of Payment of licence fee and security deposit
3. Proof of Payment of additional licence fee
4. List of vehicles along with a true copy of their licence
5. List of Drivers along with a true copy of their licence and badges
6. Proof of adequate parking spaces available for all the vehicles
7. Copy of Contract Carriage Permit (other than Electric Buses)

FORM 2

Licence for Aggregator of premium buses under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023

Name of the operator/ licence:

Name of the Applicant:

Son/ wife/ daughter of:

Full address of the place of business:

Main Office

Branch Office

is licensed to function as an aggregator of premium buses.

This licence is issued on and is valid up to

State Transport Authority

NCT of Delhi

Renewal

Renewed from to

State Transport Authority

NCT of Delhi

Secretary to Government,

NCT of Delhi, Transport Department